मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2477

04.08.2025 को उत्तर के लिए

वनों की बढ़ती कटाई

2477. श्री सनातन पांडेयः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विकास परियोजनाओं के कारण वनों की कटाई बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप जैव विविधता को नुकसान हुआ है;

(ख) क्या वन्यजीव आवासों में हस्तक्षेप के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उनकी प्रभावशीलता का आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रस्तावों पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है। केंद्र सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति या क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा के आधार पर विकास प्रस्तावों का समग्र मूल्यांकन करती है, जिसमें वनों और जैव विविधता पर उनके प्रभाव भी शामिल होते हैं। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति या क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार विकास प्रस्तावों का समग्र मूल्यांकन करती है, जिसमें वनों और जैव विविधता पर उनके प्रभाव भी शामिल होते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति देते समय वन और वृक्ष आवरण के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक वनरोपण और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली अनिवार्य रूप से निर्धारित की जाती है, इसके अतिरिक्त, वन भूमि का अपवर्तन अन्य उपशमन उपायों के कार्यान्वयन के अधीन भी है, जैसे मृदा एवं नमी संरक्षण गतिविधियां, वन्यजीव संरक्षण उपाय, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष का उपशमन, जलग्रहण क्षेत्र उपचार आदि शामिल हैं।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2023 के अनुसार, आईएसएफआर 2013 और आईएसएफआर 2023 के बीच देश में पिछले दस वर्षों के दौरान वन आवरण में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। इस प्रकार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों सहित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण देश का वन आवरण न केवल बना रहा, बल्कि पिछले दशक में इसमें शुद्ध वृद्धि भी हुई है।

*****